कोविड-19
पर विशेष अंक

खंड १६ नंबर २ अप्रैल २०२०

आरआईएस डायरी

-अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए नीतिगत अनुसंधान

महानिदेशक की ओर से

हर रोज कोविड–19 का यह संकट और गहराता जा रहा है तथा एक समाज व एक राष्ट्र के तौर पर हम इसके परिणामों को लेकर चिंतित हैं। सरकार, सभी एजेंसियों व सरकारी विभागों की ओर से इसे लेकर एक प्रभावी कार्यवाही कर रही है। इसके साथ ही राज्य सरकारें भी अपनी क्षमताओं के अनुसार इससे निपटने का भरसक प्रयत्न कर रही हैं।

हालांकि निकट भविष्य में हम आपूर्ति में बाधा की संभावनाएं देख सकते हैं और तालाबन्दी के कारण मांग को लेकर बड़ा झटका भी लग सकता है। यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर यह संकट कुछ और समय चलता रहा तो बेरोजगारी 15 से 20 प्रतिशत तक बढ़ सकती है और अर्थव्यवस्थाएं 30 प्रतिशत तक सिकुड़ सकती हैं।

अब जो प्रश्न हमारे में सबसे ऊपर है वह यह है कि वैश्विक आर्थिक स्थिति कैसे सुधर सकती है और भारत अपनी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर कैसे ला सकता है। जहां एक और विभिन्न सरकारें अपने देशों में विभिन्न प्रतिक्रियाओं का मानकीकरण कर रही है वही इससे प्रभावित विभिन्न देश वैश्विक स्तर पर आपस में समन्वय की आवश्यकता पर भी बल दे रहे हैं। लॉक डाउन के आरंभ होने से पहले से ही शोध संस्थान के तौर पर आरआईएस इस संदर्भ में विभिन्न संभावनाओं के बारे में विचार कर रहा है।

आरआईएस डायरी के इस विशेष संस्करण में आरआईएस संकाय के सदस्यों ने विभिन्न क्षेत्रों पर अपने दृष्टिकोण सामने रखे है। जिन विशेषज्ञों ने इस विषय में अपने विचार व्यक्त किए हैं वे हैंः प्रोफेसर अमिताभ कुंडू, प्रोफेसर मनमोहन अग्रवाल, प्रोफेसर मिलिंदो चक्रवर्ती, प्रोफेसर टी. सी. जेम्स व उनकी टीम, डॉ सब्यसाची साहा व डॉ प्रियदर्शी दाश। हम अपने वरिष्ठ सहायक फेलो श्री सुभोमॉय भट्टाचार्जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस संस्करण को संजोने व संपादन में हमारी सहायता की।

सचिन चतुर्वेदी

परिचय

हम दुनिया भर में अपने जीवन के अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। जिस तरह कोविड–19 वायरस दुनिया भर के हर हिस्से में फैला है उससे मानव सभ्यता एक शताब्दी के बाद एक और विश्व युद्ध का सामना कर रही है। यहां दुश्मन केवल वायरस नहीं है यहां दुश्मन वे विभाजनकारी तत्व हैं जो विभिन्न देशों में विकास लक्ष्यों के दुश्मन बनकर विद्यमान हैं और जिनके कारण इस युद्ध के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाना मुश्किल हो गया है। एक स्तर पर कोविड–19 से निपटना बहुत आसान लगता है लेकिन जैसे–जैसे हर देश इसका सामना कर रहा है वैसे ही यह भी पता चल रहा है कि किस प्रकार विकास के जो लक्ष्य जो इन देशों ने अपने लिए तय किए थे उनमें मौजूद कमियां मुश्किल का सबब बन रही हैं। इसलिए अब स्थिति यह आ गई है की कोविड–19 वायरस से उत्पन्न हुई स्थिति सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से जनसंख्या को स्वस्थ रखने के लिए इतना अधिक वजन डाल सकती है कि इन देशों की आर्थिक अस्तित्व पर ही संकट आ रहा है। इस संस्करण में लेखकों ने इस चुनौती से पैदा होने वाले प्रभावों पर विचार रखे हैं उनके अनुसार एक बड़ा प्रभाव यह हो सकता है कि वर्तमान स्वरुप के भूमंडलीकरण का अंत हो जाए। वास्तव में वर्तमान भूमंडलीकरण आधुनिक सभ्यता की सबसे प्रमुख पहचान बन गया था। वैश्वीकरण एक ऐसी आम सहमति पर आधारित था जिसमें विभिन्न देशों के

साथ संबंधों मे भरोसा होने के कारण सभी के लिए स्वीकृत कुछ ऐसे नियम व्यापार वृद्धि के लिए बन गए थे जिनसे उत्पादन व सेवाओं के प्रदान में मूल्य श्रृंखला में और गहराई आई। इसका परिणाम यह हुआ कि एक बड़े पैमाने पर वस्तु, पूंजी व व्यक्तियों का टेक्नोलॉजी की मदद से सीमाओं के आर पार आवागमन हुआ। लेकिन यह मौजूदा मॉडल की कमियां ही है जिसे कि इस वायरस ने उघाड़ कर रख दिया है।

अभी इस बात में लंबा समय लगेगा जब इस महामारी के कारण पैदा हुई परिस्थितियां और होने वाले नुकसान को हटाकर उपराष्ट्रीय स्तर पर इसके प्रभावों की स्पष्टता का अंदाजा लगाया जा सके। इस संदर्भ में पुनर्निर्माण के लिए जरूरी लागत प्रमुख रूप से सामने आएगी। हैरानी की बात है कि अभी तक इस महामारी को लेकर सर्वश्रेष्ठ प्रतिक्रियाएं एशिया, जिनमें भारत भी शामिल है, से आई हैं। अगर भारत अपनी प्रभावी प्रतिक्रिया को बनाए रख सके तो इस वैश्विक संकट को अवसर के रूप में इस शताब्दी के लिए बदल सकता है। इससे एक सार्वजनिक स्वास्थ्य का बेहतर स्वरूप सामने आ सकता है जो जनसंख्या को लेकर हमारी लाभकारी स्थिति को वाकई ही फायदे के सौदे में बदल सकता है। लेकिन कोविड–19 संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ना मुश्किल होगा और इसमें लंबा समय भी लगेगा। इस चर्चा में हम यह देखेंगे कि यह किस प्रकार किया जा सकता है। दूसरे देशों में वायरस जिस प्रकार से फैला, उससे भारत की तुलना करें तो यह संकेत मिलता है कि भारतीय तालाबन्दी ने इस महामारी को पूरी तरह से फैलने से पहले तीन सप्ताह का लाभ भारत को दिया। भारत ने यह सब करने में सफलता पाई बावजूद इसके कि उसकी चिकित्सीय क्षमता बहुत कमजोर है, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है तथा दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या उसके पास है। इससे सार्वजनिक नीति ढांचे में विश्वास पैदा होता है। आरआईएस ने इस युद्ध की मोटी मोटी रूपरेखा को जांचने का काम आरंभ किया है जिसके लिए कोई आसान मार्ग अभी मौजूद नहीं है। आगे दिए गए अध्यायों में हमारे विशिष्ट लेखकों ने विशिष्ट विषयों को उठाकर उनका विश्लेषण किया है जिससे इस युद्ध के बारे में निर्णय लेने के लिए हमें एक नया परिप्रेक्ष्य मिलेगा।

इस चर्चा में कई दिलचस्प अंतर्दृष्टियां भी हमारे सामने आती हैं लेकिन हर विश्लेषण का एक बात पर तो बल है ही कि अब विश्व व्यवस्था को एक नए सिरे से गठित करने का समय आ गया है जिससे समन्वय को व्यापक किया जा सके तथा सभी को स्वीकार्य विकास के लक्ष्य स्थापित किए जा सकें। इसी संदर्भ में यह स्पष्ट होता है कि क्यों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल ठीक बात कह रहे थे जब उन्होंने सार्क देशों को वायरस के खिलाफ लड़ाई में अपनी शक्तियों को मिलकर कई गुणा बढ़ाने के लिए कहा। इससे वैश्विक बीमा की जरूरत भी सामने आती है ताकि भविष्य में स्वास्थ्य को भी एक सर्वहितकारी वस्तु के तौर पर देखा जा सके जिससे इस प्रकार के खतरों का सामना किया जा सके। यही कारण है कि कोविड–19 के बाद की दुनिया को शोषण विहीन औद्योगिक तंत्रों की नई कल्पना करनी होगी। फिर भी यह सब शुरुआती निष्कर्ष हैं अभी इस संदर्भ में अल्प काल तथा दीर्घ काल में और अधिक विश्लेषण किया जाना बाकी है जो आरआईएस की तरफ से किया जाएगा। हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि आप इस परिचर्चा के लिए लिखे गए लेखों को पढ़ें और हमारे लेखकों के साथ इस पर बहस करें कि क्या वह मार्ग सही है जो इस युद्ध में वह इंगित कर रहे हैं। हम इस प्रकार की बहुत सारी सामग्री लेकर जल्द ही आपके सामने वापस आएंगे ताकि बौद्धिक तौर पर यह आपको पूरी तरह से इस विषय के साथ बांधे रखे जिससे हमें इस युद्ध के विभिन्न आयामों का अंदाजा हो सके।

सुभोमॉय भट्टाचार्जी
वरिष्ठ विशिष्ट फैलो, आरआईएस

कोविड–19: वैश्विक भागीदारी का समय

सचिन चतुर्वेदी

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का यह प्रस्ताव जिसके अंतर्गत उन्होंने सार्क के सदस्य देशों के नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कोविड–19 निपटने के लिए एक साझा रणनीति की बात करने के लिए उपयुक्त समय पर लिया गया अत्यंत प्रशंसनीय कदम है। इसके द्वारा जी–20 देशों के आपसी सहयोग की भावना की सही अभिव्यक्ति हुई जिसके अनुसार तय हुआ था कि जी–20 देश इस महामारी को रोकने के लिए आपस में सहयोग बढ़ाएंगे तथा समन्वय में भी वृद्धि करेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि आपसी सहयोग और समन्वय से अधिक लोगों को बचाया जा सकेगा, आर्थिक असर को भी सीमित किया जा सकेगा तथा आर्थिक स्थायित्व को बनाए रखा जा सकेगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि वैश्विक स्तर नेताओं द्वारा अपनी स्थिति स्पष्ट करने के बाद क्षेत्रीय स्तर पर आपसी सहयोग इस प्रकार के संकट से निपटने में मददगार साबित हो सकता है।

फिलहाल तो ऐसा लगता है कि सभी मोर्चों पर चुनौती और गहरा रही है। राष्ट्रवाद के उदय के कारण पहले ही भूमंडलीकरण संघर्षरत था अब तो वैश्विक सुशासन को लेकर एक और बड़ा संकट सामने आ गया है। इस संदर्भ में एक बड़ा सवाल यह है कि दुनिया अपने आप को कैसे संगठित करे क्योंकि जब आर्थिक संकट गहराता है तो आपसी भरोसे में भी भारी कमी आ जाती है।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य

दुनिया भर में शेयर बाजार औंधे मुंह गिर रहे हैं और ऐसे में इसे लेकर आर्थिक प्रभावों पर किए गए विभिन्न अध्ययन एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। इस मामले में हर किसी के अपने निष्कर्ष हैं और अपनी अपनी अनुशंसाएं। इसके अतिरिक्त अमेरिका से यात्रा व अन्य संबंधों पर अंकुश से विश्व व्यापार व्यवस्था में घबराहट और डर और भी बढ़ गया है। ओईसीडी की रिपोर्ट के अनुसार कोविड–19 के कारण सकल घरेलू उत्पाद में 4.30 प्रतिशत तक की सिकुड़न आ सकती है तथा बेरोजगारी 7 प्रतिशत तक बढ़ सकती है। इस अध्ययन में कहा गया है कि दो बार झटके लगेंगे– पहली तिमाही में 4 प्रतिशत का झटका और दूसरी तिमाही में 2 प्रतिशत का झटका। पूरी दुनिया में सकल घरेलू उत्पाद में कुल मिलाकर 2.4 प्रतिशत की कमी आने की उम्मीद है। यह भी बताया जा रहा है कि दुनिया भर में लगभग 4000 उड़ानें बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं तथा कई जगह तयशुदा समय पर माल नहीं पहुंच पाया है।

इस संदर्भ में केंद्रीय बैंकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस वैश्विक संकट से निपटने के लिए मदद उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न केंद्रीय बैंक विभिन्न प्रकार से सामने आए हैं। अमेरिकी फेड ने तरलता को बनाए रखने के लिए ट्रेजरी बिल्स के

माध्यम से 7.49 बिलियन डॉलर की मदद की है। जी–7 के वक्तव्य के अनुसार बैंक ऑफ जापान ने यह सुझाव दिया है कि भुगतान के संकट से निपटने के लिए बड़े करीब से इस संकट पर नजर रखी जाए। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना यानी पीबीसी ने मध्यावधि ऋण व्यवस्था और लोन प्राइम रेट को 10 आधार बिंदु यानी बेसिस प्वाइंट से कम कर दिया है। पीबीसी ने 300 मिलियन आरएमबी का प्रावधान उन प्रांतों के लिए करने का प्रस्ताव भी किया है जहां पर एक सीमा से अधिक यह महामारी फैली और जिसकी वजह से वहां भारी आर्थिक असर हुआ। ब्रिटिश सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए बजट में 12 अरब पाउंड का आवंटन किया है। पूरक प्रयासों के रूप में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी ब्याज दरों में आधा प्रतिशत कटौती करते हुए इसे 0.25 प्रतिशत पर लाकर खड़ा कर दिया है। यूरोपीय यूनियन पहले ही अर्थव्यवस्थाओं के लिए इसी प्रकार की अनुशंसा कर चुका है। चीन, दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं का बड़ा व्यापारिक भागीदार है। इसलिए आपूर्ति श्रृंखला में बाधा आने के कारण सभी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। चीन में लगातार खराब हो रही स्थिति के कारण पूरी दुनिया में दवाओं की कमी का अंदेशा है क्योंकि चीन अकेले ही पूरी दुनिया में इसकी 40 प्रतिशत मांग को पूरा करता है।

भारतीय परिदृश्य

ऐसा माना जा रहा है कि ऑटो, इलेक्ट्रॉनिक्स व रसायन ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जिनपर इसका प्रभाव पड़ेगा लेकिन यहां हम फिलहाल भारतीय दवाई उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। भारत सालाना 2.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एपीआई आयात करता है इसमें से 1.5 बिलियन डॉलर यानी 56 प्रतिशत अकेले चीन से आते हैं। इसके अलावा भारत द्वारा 2018–19 में 5502 मिलियन अमेरिकी डॉलर के चिकित्सा उपकरण आयात किया गया इसमे 11.2 प्रतिशत हिस्सा चीन का है। अगर हम उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी से युक्त चिकित्सा उपकरणों की बात करें तो एक्स–रे करने के लिए जो डायग्नोस्टिक रीजेंट मरीजों को दिए जाते हैं उसके मामले में भारत चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर है। इस विशिष्ट उत्पाद श्रेणी में भारत ने 2018–19 में लगभग 48.38 मिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात किया, इसमें से चीन से आने वाला आयात 32.47 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 75 प्रतिशत था।

स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए भारत को फेस मास्क तथा अन्य चिकित्सा उपकरणों के घरेलू उत्पादन को हर हालत में बढ़ाना होगा। इसके साथ ही भारत के पास दुनिया भर में इन उत्पादों के लिए पैदा हो रही मांग को पूरा करने का भी सुनहरा मौका है खासकर अमेरिका और फिलीपींस से आ रही मांग के चलते। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार फेस मास्क की मांग में 100 गुना की वृद्धि हो रही है (यूएन न्यूज 7 फरवरी 2020)। इसके अलावा भारत को अपने वैज्ञानिक मानवीय संसाधनों, शोध व विकास, मानकीकरण व गुणवत्ता नियंत्रण तथा बेहतर टेक्नोलॉजी में निवेश कर अपनी घरेलु क्षमताओं को इस क्षेत्र में और मजबूत करना चाहिए।

दुनिया भर के नेतृत्व को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस सुझाव को गंभीरता से लेना चाहिए जो उन्होंने क्षेत्रीय संदर्भों में दिया है। यह तो स्पष्ट ही है कि इस समस्या का समाधान कम से कम राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता तो नहीं हो सकता है। हमें मिलकर एक साथ चलते हुए पूरी दुनिया में सर्वहितकारी वस्तुओं को यानी कि पब्लिक गुड्स का निर्माण करना होगा। खासकर कनेक्टिविटी तथा राष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सा व अन्य विशिष्ट संस्थाओं व सामूहिक शोध व विकास के प्रयासों को मजबूत करने तथा उनका संवर्धन करने के लिए ही हम सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है।

दुनिया के अन्य देशों में फंसे हुए लोगों को निकाल कर वापस लाने के अभियानों पर भी और ज्यादा जोर देने की जरूरत है। भारत ने इस संदर्भ में कुछ प्रयास किए हैं लेकिन इनका स्तर और व्यापक करने की जरूरत है। निश्चित ही दूसरे देशों के साथ भागीदारी में यह संभव हो सकता है। अब तक घर वापसी के इन अभियानों में भारत ने 1031 लोगों को वापस अपने देश लौटाया है, इनमें से 48 लोग ऐसे हैं जो दूसरे देशों से संबंध रखते हैं मसलन मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश, चीन, यूएस, मेडागास्कर, श्रीलंका, नेपाल, दक्षिण अफ्रीका व पेरू।

निश्चित ही इस प्रकार के प्रयासों की दुनिया भर में वैश्विक स्तर पर जरूरत है। यह भी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए बुनियादी ढांचे को लेकर एक दूसरे की मदद की जाए। विशेषज्ञों के नेतृत्व में संकट से निपटने संकट प्रबंधन के लिए की दृष्टि से भारत ने अपने वरिष्ठ चिकित्सकों व वैज्ञानिकों को माले तथा तेहरान भी विभिन्न दलों में भेजा है।

इन प्रयासों को भारत के उन व्यापक वैश्विक प्रयासों के हिस्से के तौर पर देखा जाना चाहिए जो वह दक्षिणीय सहभागिता के ढांचे में कर रहा है। केवल दक्षिण ही नहीं इससे आगे बढ़कर भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से 4 डॉक्टरों की एक टीम को रोम भी भेजा गया। उनके पास पर्याप्त सामग्री तथा रीजेंट थे जिससे वे वहां रह रहे भारतीयों के खून के नमूने ले सके जिससे कि आगे भारत में उनकी जांच की जा सके। यह सब भारत अपने अनुभव के आधार पर कर रहा है। आईसीएमआर ने जांच की अपनी क्षमता को बढ़ाते हुए अब 52 प्रयोगशालाएं स्थापित कर दी हैं जहां कि इस वायरस को लेकर परीक्षण किया जा सकता है।

सामूहिक शोध व विकास के प्रयासों को शीर्ष प्राथमिकता देनी चाहिए। भारत ने अपने वैज्ञानिकों उपकरणों आदि को बाहर भेजा है और वहां से भारतीय वैज्ञानिक वे नमूने लेकर आए हैं जिनका कि भारत में परीक्षण हो रहा है। अभी तक ईरान से 1199 नमूने एकत्रित किए गए और उन्हें भारत टेस्टिंग के लिए लाया गया है।

हाल ही में पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एनआईबी ने यह जानकारी दी कि कोरोनावायरस को अलग कर लिया गया है पुणे स्थित इस संस्थान से आई यह खबर अत्यंत आशा जनक है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार इस संस्थान ने इस वायरस के 11 विभिन्न प्रकारों को अलग करने में सफलता पाई है। इस प्रकार की अलग पहचान करना आवश्यक है क्योंकि इससे निदान के लिए किसी भी प्रकार की शोध की यह पहली आवश्यकता है। इस लंबी अंधेरी सुरंग के मुहाने पर इस प्रकार के प्रयासों से चारों ओर से छाए गहन अंधेरे में सूरज की किरण रोशनी की किरण स्पष्ट दिखाई देती है।

महानिदेशक, आरआईएस। इससे पूर्व यह लेख 25 मार्च 2020 को *फाइनेंशियल एक्सप्रेस* में प्रकाशित हुआ था।

तालाबन्दी,कोविड–19 को रोकना तथा अंतरराज्य प्रवासियों के हितों की देखरेख

अमिताभ कुंडू

भारत में ज्यादातर लोगों ने 21 दिन के तालाबन्दी का स्वागत किया है। इसका कारण यह भी है कि दुनिया भर में कई अन्य देश जिनका आर्थिक स्तर हमसे बेहतर है वहां भी बड़ी संख्या में कोविड–19 से प्रभावित मामलों की जानकारी सामने आ रही है। लेकिन सामुदायिक स्तर पर लॉक डाउन के क्या प्रभाव हो सकते हैं यह अभी स्पष्ट नहीं है। क्या इसका मतलब यह है कि हर व्यक्ति जिस स्थान पर है वहीं पर बना रहे, वह उस परिसर से बाहर ना आ पाए चाहे उसे दवा, भोजन व अन्य आवश्यक वस्तुएं खरीदनी हो या उसके घर में कोई आपातकालीन स्थिति हो या फिर वह अपनी नियमित पैदल सैर के लिए बाहर जाना चाहता हो? अगर ऐसा है तो क्या हम लोगों के घरों तक आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं को पहुंचाने की सुविधा विकसित कर चुके हैं और क्या इस सारे क्रय–विक्रय की प्रक्रिया की सुरक्षा का इंतजाम भी किया गया है? दूसरी ओर अगर इस तालाबन्दी के दौरान अपने घर या कॉलोनी से किसी जरूरी काम के लोगों को बाहर जाने की अनुमति मिलती है तो हम कैसे सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रावधान का दुरुपयोग ना हो और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे इसकी सजा दी जाए। अगर शहर या राज्य के बाहर अपवाद स्वरूप किसी को यात्रा करने की अनुमति देनी है तो यह प्रक्रिया क्या होगी इसे भी संस्थागत करने की आवश्यकता है। तीस करोड़ परिवारों के लिए 21 दिन का लॉकडाउन आसान नहीं है। उन्हें किसी भी जरूरत के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। लेकिन वर्गों में बंटे हुए समाज में किसी खास को बाहर जाने की अनुमति देना अपने आप में कुछ स्वार्थी हितों के हाथ में खेलने जैसा भी हो सकता है।

सावधानी रखना और घबराना नहीं इसके बीच की रेखा बहुत स्पष्ट नहीं है। इसे बनाए रखने के लिए कहना तो आसान है पर वास्तविकता में उस पर अमल करना मुश्किल है। हम देखते हैं कि यह रेखा कई मामलों में धूमिल हो गई है खासकर नीतिगत घोषणाओं, प्रशासनिक आदेशों व कोविड–19 को लेकर जमीनी स्तर पर प्रबंधन के मामले में। इससे आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आवाजाही प्रभावित हुई है और लोग भी प्रभावित हुए हैं। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि उचित जानकारी उपलब्ध रहे तथा प्रबंधन व्यवस्था में पारदर्शिता हो। लेकिन दुर्भाग्यवश फिलहाल तो यह दोनों ही इन परिस्थितियों की भेंट चढ़ गए लगते हैं।

इससे पहले नोटबंदी के दौरान भी इसी प्रकार की घबराहट भरी प्रतिक्रिया सामने आई थी और उस समय भी बहुत सी चुनौतियां सामने थी लेकिन विभिन्न समूहों ने एक दूसरे के साथ मिलकर इन समस्याओं का सामना किया। उन्होंने आपसी भरोसे के आधार पर वस्तुओं का आदान प्रदान किया और कमजोर वर्गों को बहुत ज्यादा परेशानी से बचाने में सफलता हासिल की। लेकिन वर्तमान संकट में ऐसा होना शायद संभव न हो पाए। बिना समाज की मदद के सरकार अपने दम पर तालाबन्दी के दौरान इन सब विषयों की देखरेख नहीं कर सकती है। यहां तक कि नवरात्र के दौरान नौ परिवारों को मदद करने की जो बात कही गई है उससे भी हम बहुत से परिवारों को असुरक्षित संक्रमण के खतरे से रूबरू कर देंगे इसलिए इसे संस्थागत करना जरूरी है। जब तक वस्तुओं व सेवाओं की उपलब्धता व

उनके प्रबंधन संबंधी मुद्दों को ठीक से निपटा कर उन्हें निचले स्तर पर प्रशासन व आम लोगों को संप्रेषित नहीं किया जाएगा तब तक इसके प्रबंधन को लेकर गंभीर समस्याएं बनी रहेंगी। इस संदर्भ में विरोध तथा समूहों के बीच सामुदायिक स्तर पर हिंसा को लेकर भी चिंता करना जरूरी है।

समुदायों व सामाजिक संगठनों को बड़े पैमाने पर इस मामले में अपने साथ जोड़ना और सक्रिय करना अपने आप में सुरक्षा संबंधी दिक्कतें पैदा कर सकता है। इसके साथ ही इसका परिणाम यह भी हो सकता है कि वे लोग जिनकी विशेष आवश्यकताएं हैं या जो कि इस समय एक संकट में फंस गए हैं मसलन दिहाड़ी मजदूर, बीमार व दिव्यांग लोगों की देखरेख करने वाले तथा वे लोग जो दुर्घटना वश अपने परिवारों से अलग हो गए हैं, उनके हित नजरअंदाज हो जाएं।

कुछ विशेष समस्याओं के लिए निजी सेक्टर, सरकार व सामाजिक संगठन आपस में भागीदारी कर सकते हैं। यह भागीदारी अत्यंत प्रभावी साबित हो सकती है तथा सुरक्षा संबंधी खतरों को भी कम कर सकती है। तालाबन्दी के दौरान एक प्रमुख समस्या आवागमन की है। लगभग छह करोड़ पचास लाख अंतर राज्य प्रवासी हैं जिनमें से 33 प्रतिशत कामगार हैं। इनमें से 30 प्रतिशत अनियमित कामगार हैं और 30 प्रतिशत ऐसे हैं जिन्हें अनौपचारिक क्षेत्र में नियमित रोजगार मिलता है। इसका मतलब यह है कि लगभग 1.2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन पर रोजगार खोने का खतरा मंडरा रहा है। वह उन राज्यों में रहते हैं जहां वे पैदा नहीं हुए हैं। कमजोर वर्ग में उन 80 लाख रेहड़ी पटरी वालों को भी शामिल किया जा सकता है जो सड़क या फुटपाथ पर सामान बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। इनमें से बहुत से हैं जिनकी आजीविका का माध्यम समाप्त हो गया है। वे जहां रह रहे थे उन जगहों को छोड़ रहे हैं तथा विभिन्न शहरों में अभी फंसे हुए हैं। सरकार कोरोना प्रभावित देशों से भारतीयों को वापस ला रही है। यह बिल्कुल उचित है लेकिन सरकार इन प्रवासी मजदूरों को परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध करा सकती थी। वे किसी भी हाल में अपने घर लौटना चाहते हैं। सरकार अगर चाहे तो यह सुनिश्चित कर सकती थी कि उन्हें भीड़भाड़ भरे वाहनों में यात्रा न करनी पड़े और वे अपने लिए ही कोई विकल्प ढूंढने के लिए मजबूर ना होना पड़े।

राज्य सरकारों के निजी कारपोरेट सेक्टर तथा गैर सरकारी संगठन, जिनमें कामगारों के संगठन भी शामिल हैं उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बड़े पैमाने पर रोजगार का नुकसान ना हो। कुछ केंद्रीय कोष का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मसलन हाल ही में अनुमति दी गई है कि राज्य 29000 करोड़ के आपदा राहत कोष का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही निजी कंपनियों के संसाधनों का भी इस्तेमाल इस उद्देश्य से किया जा सकता है। यह सब करते हुए सामाजिक संगठनों को इन प्रयासों में शामिल किया जा सकता है जिनमें यात्रा, भोजन, निवास तथा मेडिकल चेकअप के लिए वे सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। यह सब आवश्यक अवधि तक राज्य सरकारों के निरीक्षण में किया जा सकता है। ऐसे प्रयास किए जाने चाहिएं जिससे कि इनमें से अधिकतर लोग जहां हैं वहीं रुके रहे और उनकी देखरेख की जाए। उत्तर प्रदेश और बिहार की कुल अंतर राज्य प्रवासियों में हिस्सेदारी क्रमश 25 व 14 प्रतिशत है। इसके उपरांत राजस्थान व मध्य प्रदेश आते हैं। इन दोनों राज्यों की हिस्सेदारी अंतर राज्य प्रवासियों में 5 प्रतिशत से अधिक है। अगर ये प्रवासी वापस जाते हैं तो जो समस्याएं वह रास्ते में झेलेंगे उसके उपरांत इस महामारी को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होगा। वे अपने परिवारों में भी बेरोजगार के रूप में रहेंगे। जिन स्थानों पर अभी वे हैं, वहीं पर उनकी देखभाल करना यह सुनिश्चित करने में निश्चित रूप से मदद करेगा कि कोविड–19 हमारे देश के पिछड़े क्षेत्रों में भीतर तक ना पहुंच जाए।

विशिष्ट फैलो, आरआईएस

अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव

मनमोहन अग्रवाल

अल्पकाल

कृषिः कृषि क्षेत्र के लिए मुख्य चिंता का विषय है कि किस प्रकार सब्जियों व फलों की आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखा जाए। यह भी सवाल है कि बड़ी संख्या में क्रेताओं तथा विक्रेताओं की उपस्थिति के बिना थोक बाजार किस प्रकार काम कर पाएंगे।

उद्योगः सभी तीनों प्रकार के उद्यमों में उत्पादन तो प्रभावित होगा लेकिन यह अलग अलग तरीके से सामने आएगा । एमएसएमई सहित सभी उद्यमों के लिए सवाल यह है कि उनकी देनदारियां क्या है।

ऋणः अगर हम उन्हें दिवालिया होने देंगे तो इससे उन्हें ऋण देने वालों पर बहुत खराब प्रभाव पड़ेगा, खासकर बैंकों पर। इसलिए बेहतर यह होगा कि उन्हें ब्याज देने से कुछ समय तक छूट दी जाए। इस संदर्भ में एनपीए को लेकर मौजूदा व्यवस्था में बैंकों द्वारा दिए ऋणों की ओर ध्यान देना होगा।

वेतनः क्योंकि मांग और इसकी वजह से उत्पादन भी सीमित हो जाएगा तो वह अपनी देनदारियों को कामगारों को हटाकर कम कर सकते हैं। लेकिन इससे बचना चाहिए क्योंकि इसके सामाजिक प्रभाव तो होंगे ही इससे अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाना भी मुश्किल हो जाएगा। जब भी अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पर आएगी इन फर्मों को नए कामगारों को लेना पड़ेगा और उन्हें प्रशिक्षित करना अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया है जो बहुत समय लेती है। इसलिए सबसे बेहतर तो यह होगा कि अगर इन कंपनीयों को इस बात के लिए राजी किया जा सके कि वे इन कामगारों को काम पर बनाए रखें। कुछ यूरोपीय देश इसके लिए कामगारों के 50 से 75 प्रतिशत वेतन को अपनी ओर से निजी उद्यमों को दे रहे हैं। निश्चित ही यह लागत पूरी तरह से सरकार को वहन नहीं करनी पड़ रही है क्योंकि ऐसा करने के बाद सरकार को बेरोजगारी भत्ते नहीं देने पड़ेंगे। इस बात की समीक्षा होनी चाहिए कि इस प्रकार की योजना को भारतीय परिस्थितियों के संदर्भ में किस प्रकार क्रियान्वित किया जा सकता है।

वित्तीय लागतें

आर्थिक मंदी के कारण प्रत्यक्ष कर, व्यक्तिगत कर, कॉरपोरेट तथा अप्रत्यक्ष कर, जीएसटी से आने वाली आय में कमी आएगी। अगर आर्थिक गतिविधियों को बनाए रखा जा सकेगा ऐसे में ज्यादा कर संग्रह से सामाजिक व्यय के प्रभाव को कम किया जा सकेगा। यहां महत्वपूर्ण सवाल यह है कि घाटे को कितना बढ़ाया जाए जिससे आर्थिक गतिविधियों में आ रही गिरावट से निपटा जा सके। ज्यादातर विकसित देश अपने यहां रोजगार को बनाए रखने तथा कंपनियों की मदद करने के लिए जीडीपी का पांच से 10 प्रतिशत खर्च करने की योजना बना रहे हैं। अमेरिका ने आरंभ में सोचा कि एक खरब डॉलर का आवंटन इसके लिए काफी होगा लेकिन कांग्रेस द्वारा पारित किए गए विधेयक के अनुसार अब इस खर्च को दुगना कर दो खरब डॉलर किया जा चुका है जो अमेरिकी जीडीपी का लगभग 10 प्रतिशत है। स्थिति की गंभीरता को लेकर किस प्रकार सभी में आम सहमति है उसका अंदाजा इस बात से लग सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा द्वारा दिए गए तुलनात्मक रूप से बहुत छोटे पैकेज 787 मिलियन डॉलर, जो 2009 में दिया

गया था, उसके विरोध के बिल्कुल उलट इस आवंटन को पारित करने में सबकी आम सहमति थी।

मध्यावधि

कृषि : समस्या तब होगी जब फसल कटाई के लिए तैयार होगी। क्या उस समय फसल की कटाई के लिए पर्याप्त संख्या में कामगार मिलेंगे या नहीं, यह मुद्दा विशेष रूप से बड़े किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह भी देखना होगा कि कटी हुई फसल की बिक्री और उसकी स्टोरेज के लिए किस प्रकार से इंतजाम करने होंगे। यह भी देखना होगा की बुवाई का अगला मौसम आने तक किस प्रकार से सप्लाई चेन को सुचारू बनाए रखा जाए।

उद्योग व रोजगार : आर्थिक गतिविधियों में कमी आने से रोजगार व कल्याण संबंधी गतिविधियों पर जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है उसे कम से कम करने के लिए पीडीएस, मनरेगा व अन्य पेंशन स्कीमों को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करना होगा। जिनकी नौकरियां जा रही हैं उनके लिए आय का इंतजाम करना आवश्यक होगा। ऐसे कामगारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, जिन में दिहाड़ी मजदूर भी शामिल है, हमें अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस को और ज्यादा व्यापक करना होगा।

वित्तीय सेक्टर : उत्पादन व्यवस्था में जितने कम अवरोध आएंगे उतनी ही जल्दी आर्थिक गतिविधियां दोबारा अपनी पटरी पर लौट आएंगीं और इससे दीर्घकाल में ज्यादा कर संग्रह किए जा सकेंगे। भारतीय संदर्भों में सरकारी खर्च का बहुगुणात्मक प्रभाव ज्यादा होगा क्योंकि पूरक आय ज्यादातर उन गरीब वर्गों को जाएगी जिनकी उपभोग करने की प्रवृत्ति ज्यादा है। भारत के मामले में घाटा अगर 3 से 6 प्रतिशत तक बढ़ जाता है तो वह भी पर्याप्त होगा। इस मामले में लचीलापन बनाए रखना होगा क्योंकि आगे चलकर और मदद की आवश्यकता भी पड़ सकती है।

ऐसे समय में जब उत्पादन व्यवस्था उतार पर है, बहुत बड़े पैमाने पर मांग का सृजन करना महंगाई की दर को बढ़ाने का खतरा भी पैदा करता है। इससे निपटने के लिए दो कदम उठाए जा सकते हैं— सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करना तथा इस व्यवस्था में कुछ नई आवश्यक वस्तुओं को भी शामिल करना। दूसरा कदम है, ज्यादा आयात करना। लेकिन अधिक आयात के लिए अभी से योजना बनानी होगी ताकि जब घरेलू आपूर्ति से घरेलू मांग अधिक हो जाए उस समय ये आयातित वस्तुएं उपलब्ध है। सौभाग्यवश हमारे पास अभी इतने रिजर्व हैं कि अधिक आयात का भार हम वहन कर सकते हैं। इस संदर्भ में चालू खाता तथा भुगतान संतुलन पर पड़ने वाले प्रभावों को अनुमानित पूरा करना होगा। ये घाटे न केवल अधिक आयात के कारण होंगे बल्कि इनमें कमजोर निर्यात के कारण भी इजाफा होगा क्योंकि दुनिया भर में मांग गिर रही है और हमारी उत्पादन क्षमताएं पहले ही बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी हैं। इसलिए वर्तमान में ही अधिक ऋण को लेकर प्रावधान करने होंगे बजाय इसके कि हम तब तक इंतजार करें जब तक कि घाटा बढ़ नहीं जाता।

रिजर्व बैंक की भूमिका : ऐसे अनिश्चित समय में मौद्रिक नीति को कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए इस्तेमाल करने के बजाय पर्याप्त तरलता बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन साथ ही इस समय रिजर्व बैंक के निरीक्षण को और मजबूत करने की जरूरत है ताकि वित्तीय संस्थान ऐसे कदम न उठाएं जिनमें स्थायित्व की कमी है।

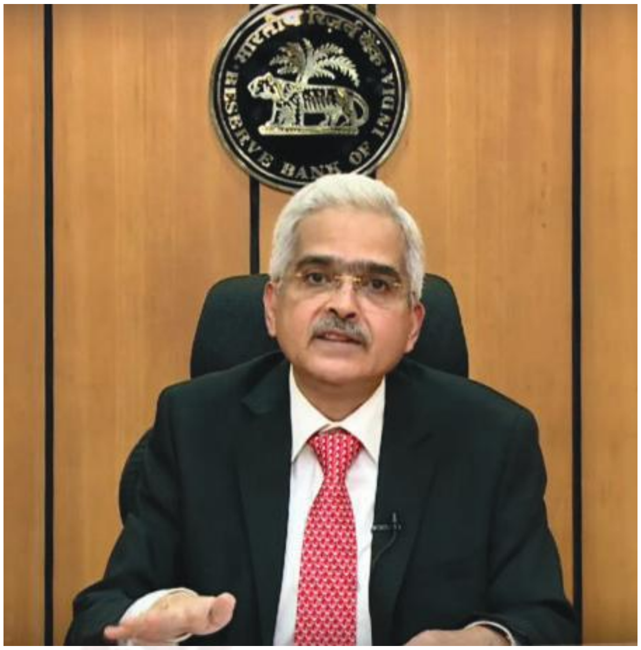

वरिष्ठ विशिष्ट फैलो, आरआईएस

वैश्विक महामारी बीमा कोष के लिए आवश्यकता

मिलिंदो चक्रवर्ती

जिस प्रकार से कोविड–19 पूरी दुनिया में तेजी से फैला है उससे यह स्पष्ट होता है कि हो सकता है किसी भी व्यक्ति का रुग्णता और मृत्यु दर प्रोफाइल उन कारकों से प्रभावित न हो जो उसके नियंत्रण में नहीं है। सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए जो आह्‌वान किया गया है – हालांकि हम जो कर रहे हैं वह सामाजिक दूरी नहीं बल्कि भौतिक दूरी है – वह जल्दबाजी में लिया हुआ एक अल्पकालीन नीतिगत प्रयास लगता है। इसका उद्देश्य है वैयक्तिक अस्तित्व के आसपास एक सुरक्षात्मक कवच तैयार करना और ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ संपर्क को तोड़ना अथवा रोकना जिससे कि वायरस को फैलने से रोका जा सके। बेशक यह रणनीति उस नीतिगत व्यवस्था का ही हिस्सा हो सकती है जो दशकों से स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत पूरा जोर उपचार पर दे रही है, जबकि पूरा ध्यान रोकथाम पर होना चाहिए।

स्वास्थ्य सेवाओं का निजी वस्तु के रूप में उभरना

स्वास्थ्य नीति को लेकर जो उपचारात्मक दृष्टिकोण है उसके अनुसार यह सुनिश्चित करना होता है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो गई है तो उसका उपचार किया जाए। यह उपचार संबंधित व्यक्ति की क्रय क्षमता पर आधारित होता है और इस प्रकार स्वास्थ्य सेवाएं लगभग एक निजी उत्पाद में बदल जाती हैं। यह सब इन मान्यताओं पर आधारित होता है कि इस व्यक्ति का रुग्णता और मृत्यु दर प्रोफाइल दूसरों पर निर्भर नहीं करता है। इस व्यक्ति की बीमारी का इलाज उसे भुगतान करने की क्षमता के आधार पर उपलब्ध है। इस प्रकार की सोच ऐसी स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने में मदद करती है जो तभी प्रभावी हो सकती है अगर वह निजी एजेंट के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाए। पिछली शताब्दी के अंतिम दशक से यह देखा जा रहा है कि भारत की स्वास्थ्य सेवाएं एक निजी उत्पाद में बदल रही है इस बीच विभिन्न अध्ययनों से यह पता चला है की उपचारात्मक दृष्टिकोण से लोगों की देखभाल करने की लागत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अक्सर यह लागत आम भारतीय नागरिकों की भुगतान करने की क्षमता से कहीं अधिक है।

दुर्भाग्यवश ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से असफल होती है। जब कोई ऐसा संकट आता है जिसमें व्यक्तिगत रुग्णता व मृत्यु दर प्रोफाइल दूसरों से स्वतंत्र नहीं होता है। मैं एक ऐसी संक्रामक महामारी की बात कर रहा हूं जो रोकथाम से संबंधित स्वास्थ्य नीति की आवश्यकता को स्पष्ट कर रही है क्योंकि इसका उपचार करना संभव नहीं है। इस समय इस वायरस के रोकथाम संबंधी समाधान के रूप में ऐसे तालाबन्दी के बारे में ही सोचा जा रहा है जिससे व्यक्तिगत लोगों के आसपास एक ऐसा सुरक्षात्मक कवच बन जाएगा जिससे उन्हें इस समस्या से दो–चार नहीं होना पड़ेगा। हालांकि इसके कारण ऐसी संभावना बन रही है कि लाखों लोगों का रोजगार भी प्रभावित होगा क्योंकि हम एक संभावित ''आर्थिक तालाबन्दी'' की तरफ देख रहे हैं।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की है जो ऐसे अल्पकालीन आर्थिक समर्थन के उपायों को अपने में लिए हुए हैं जिससे उनको मदद मिलेगी जो इस तालाबन्दी के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। जी–20 के नेतृत्व में भी इस आर्थिक संकट से उबरने के लिए खरबों डॉलर की प्रतिबद्धता जाहिर की है। लेकिन अभी यह तय नहीं है की जिस राशि की प्रतिबद्धता जाहिर की गई है वह इस महामारी के दीर्घकालीन प्रभावों को, जिसमें आर्थिक व सामाजिक प्रभाव दोनों शामिल हैं, से निपटने में कारगर साबित होगी।

आशा करनी चाहिए कि यह महामारी एक सीमित समय के अंदर समाप्त हो जाएगी। कोविड–19 से प्रभावित होने वालों के लिए इस वायरस के खिलाफ प्रतिकारक यानी एंटीडॉट बना दिए जाएंगे। जीएवीआई जैसे संगठन उन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाएंगे जिनसे की ऐसी वैक्सीन बनाई जा सकती हैं जो आर्थिक व सामाजिक रुप से कमजोर वर्गों को कम दामों पर या सब्सिडी के साथ कुछ समय तक दी जा सकती हैं। खासकर ऐसा तब तक किया जा सकता है जब तक की जिन देशों में ऐसा किया जा रहा है वे उस स्थिति में नहीं पहुंच जाते कि वह इस वैक्सीन

को अपने संसाधनों से उत्पादित करने की कीमत को वहन कर सकें। इस बात की भी पूरी संभावना है कि हम जल्द ही इसका प्रभाव भूल जाएंगे और फिर से उसी उपचारात्मक दृष्टिकोण के साथ पुराने ढर्रे पर लौट जाएंगे।

सार्वजनिक वस्तु के तौर पर स्वास्थ्य सेवाओं को विकसित करनाः वैश्विक महामारी बीमा कोष की स्थापना

दुनिया भर में जिस प्रकार से यह महामारी फैली है उससे इस बात का एहसास भी हुआ है कि स्वास्थ्य सेवाओं को केवल एक निजी वस्तु के तौर पर नहीं लिया जा सकता। वैश्विक स्तर पर हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि स्वास्थ्य सेवाएं एक सर्वहितकारी वस्तु के तौर पर उपलब्ध हो। विकास के सतत लक्ष्यों में जो तीसरा लक्ष्य है वह अच्छे स्वास्थ्य और सबके कल्याण की बात करता है। जिसका अर्थ है कि स्वास्थ्य सेवाओं को एक सार्वजनिक वस्तु के तौर पर देखना चाहिए। हालांकि प्रत्येक देश को इस संदर्भ में अपना लक्ष्य खुद निश्चित करना है और एक तय समय सीमा के भीतर इस लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। कोविड–19 और दुनिया भर में इसके फैलाव से इस बात का हमें एहसास हुआ है कि सतत विकास के तीसरे लक्ष्य की एक वैश्विक रणनीति होनी चाहिए और एक ऐसी वैश्विक नीति स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में होनी चाहिए जहां रोकथाम संबंधी परिप्रेक्ष्य पर ज्यादा बल दिया जाए।

जी–20 शिखर ने 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि देने की प्रतिबद्धता की घोषणा की है जिससे कि इस महामारी से उत्पन्न होने वाले वैश्विक आर्थिक झटके से निपटा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक शुरुआत की है जिससे सार्क के स्तर पर एक क्षेत्रीय कोष बनाया जा सके। बहुत से सदस्य देशों ने इस कोष में योगदान देने की प्रतिबद्धता जाहिर की है। लेकिन अब यह समय है कि वैश्विक नेता इस बात की जरूरत को महसूस करें कि हमें एक दीर्घकालीन व्यवस्था की शुरुआत करनी होगी ताकि भविष्य में आने वाली महामारियों से निपटा जा सके। ऐसे में एक सुझाव यह भी है कि एक वैश्विक महामारी बीमा कोष बनाया जाए जिसमें सभी देश अपना योगदान दें। ऐसे योगदान के बारे में तय करने के लिए चर्चा की जा सकती है और यह डिसेबिलिटी एडजेस्टेड लाइफ जो इन देशों में है, उसके अनुरूप हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक जीवन के एक डिसेबिलिटी साल को स्वस्थ जीवन के खोए हुए एक साल के बराबर माना जा सकता है मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं और एक आदर्श स्वास्थ्य परिस्थिति के बीच में अंतर नापने के लिए हम पूरी जनसंख्या में इन डिसेबिलिटी सालो को जोड़ कर एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। जब हम आदर्श स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हमारा मानना है कि संपूर्ण जनसंख्या लंबे समय तक बिना बीमारी एवं अपंगता के जी सके, किसी बीमारी या स्वस्थ स्थिति के लिए डिसेबिलिटी एडजेस्टेड लाइफ की गणना करने का तरीका यह है की यह समय से पहले मृत्यु अथवा विशाल जो अपंगता के कारण खो गए उनके कुल समग्र के रूप में सामने आती है।

लगभग 198 देश इस महामारी से प्रभावित है। अगर हम बहुत ही सीमित योगदान की बात भी करें तो भी प्रत्येक देश द्वारा अगर मात्र दस लाख डॉलर का योगदान भी इस कोष में देता है तो हमारे पास सालाना दो अरब अमेरिकी डॉलर का कोष होगा। एक बार ऐसा कोष स्थापित हो जाने पर विभिन्न निजी दानदाताओं से इसमें और योगदान मिल सकता है जिससे कि इस का आकार काफी बड़ा हो सकता है। इसके बाद समय के साथ इस प्रकार के क्षेत्रीय कोष भी बनाए जा सकते हैं। दक्षिणीय सहयोग की भावना का समर्थन करने वाले इसी प्रकार का एक कोष पूरे विश्व में दक्षिण के लिए बना सकते हैं।

महामारी नियमित अंतराल पर नहीं आती है। अभी इस मामले को लेकर अनिश्चितता है कि क्या जलवायु परिवर्तन के कारण इस प्रकार की परिस्थितियां बार–बार उत्पन्न होंगी। अगर इस प्रकार की महामारी कई देशों में आती है तो इससे निपटने के लिए सभी देशों से सालाना एक कोष के लिए योगदान लिया जा सकता है। क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं एक के बाद एक नहीं होती हैं और उसमें एक लंबा अंतराल भी आता है ऐसे में यह कोष हर साल अपने में ही बड़े पैमाने पर बढ़ सकता है क्योंकि उससे सालाना खर्च इतना अधिक नहीं होगा। अगर इस की राशि को मौद्रिक उपकरणों में ठीक से निवेश किया जाए तो आने वाले सालों में यह कई गुणा बढ़ जाएगा जिससे कि वैश्विक स्वास्थ्य आपदाओं से निपटने में मदद मिलेगी। इस कोष का एक हिस्सा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में शोध व विकास के लिए भी उपयोग किया जा सकता है जिससे कि नई वैक्सीन और दवाओं को विकसित किया जा सके। इस प्रकार की पहल से बौद्धिक संपदा अधिकार यानी आईपीआर के विवादास्पद मसले को भी हल करने में मदद मिलेगी क्योंकि आईपीआर से स्वास्थ्य सेवाओं को निजी उत्पाद में बदलने की संभावना बढ़ती है। इससे कुछ निजी निवेशकों के हाथ में बहुत सारा लाभ आने की संभावना बनी रहती है। यह प्रस्तावित कोष निजी निवेशकों के साथ प्रतियोगी के रूप में काम करेगा, खासकर जब दवाओं के क्षेत्र में नवोन्मेष की बात होगी। यह नवोन्मेष में अपने प्रयासों के लिए किसी अतिरिक्त लाभ का प्रयास नहीं करेगा। इसके द्वारा विकसित उत्पादों का आईपीआर पूरे वैश्विक समुदाय के पास होगा।

विश्व स्वास्थ्य संगठन और जीएवीआई द्वारा एक वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसके लिए रोकथाम व उपचार दोनों की दृष्टि से मानक प्रोटोकॉल बनाने का काम कर रहा है। जीएवीआई भी पूरी दुनिया में सबके लिए टीकाकरण सुनिश्चित करने का काम प्रभावी ढंग से कर रहा है। प्रस्तावित वैश्विक महामारी बीमा कोष न केवल महामारी के दौरान वैश्विक समुदाय को मुश्किलों से निपटने में मदद करेगा बल्कि स्वास्थ्य के लिए वैश्विक शोध व विकास हेतु सस्ते संसाधन भी उपलब्ध करवाएगा जिससे कि आईपीआर के विवादास्पद मुद्दों से निपटा जा सके। ये मुद्दे उन लोगों को बहुत प्रभावित करते हैं जिनके पास नवोन्मेष को लेकर कोई अधिकार नहीं है पर अपने अस्तित्व के लिए वे उन पर निर्भर हैं। एक वैश्विक महामारी बीमा कोष वाकई ही सतत विकास के तीसरे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सही मायने में मदद करेगा जिससे यह सुनिश्चित होगा कि स्वास्थ्य सेवाएं सही मायने में वैश्विक सार्वजनिक वस्तु के रूप में स्थापित हो सकें।

विजिटिंग फेलो, आरआईएस व प्रोफेसर, ओ.पी.जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी

कोविड–19 व भारतीय दवाई उद्योग

टी. सी. जेम्स

भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रमुख समस्याएं हैं पर्याप्त बुनियादी ढांचा, चिकित्सा संबंधी वस्तुओं तथा मानव संसाधनों का अभाव। तालिका 1 में इस संबंध में विवरण दिया गया है। प्रति 1000 व्यक्तियों पर अस्पताल में बिस्तरों का वैश्विक औसत 2.7 है, जबकि हमारे यहां यह औसत 0.7 है। प्रति 1000 जनसंख्या पर नर्सों व दाइयों का वैश्विक औसत 3.4 है जबकि भारत में यह औसत 2.1 है। मौजूदा कोरोना वायरस महामारी से बुरी तरहं से प्रभावित इटली में यह औसत 5.86 है जिसे एक अच्छा औसत कहा जा सकता है। इसी प्रकार से प्रति 1000 जनसंख्या पर चिकित्सकों का वैश्विक औसत 1.50 है जबकि भारत में यह औसत 0.78 है। इटली में यह औसत 4.09 है लेकिन इसके बावजूद वह इस विकराल समस्या का सामना कर रहा है।

तालिका 1: भारत और विश्व में स्वास्थ्य सेवा का तुलनात्मक विश्लेषण

सूचक	भारत		विश्व
	निरपेक्ष रूप से	अनुपात	
प्रति 1000 जनसंख्या पर चिकित्सक	10,44,420	0.78	1.50
प्रति 1000 जनसंख्या पर नर्स और दाई	28,11,900	2.10	3.42
अस्पतालों में प्रति 1000 जनसंख्या पर बेड	8,75,000	0.7	2.7

नोटः *उपलब्ध नवीनतम वर्ष के लिए लिया गया डेटा,*

स्रोतः *विश्व विकास संकेतक डेटासेट, विश्व बैंक*

विश्व स्वास्थ्य संगठन की अनुशंसा के अनुसार प्रति 1000 जनसंख्या पर एक डॉक्टर होना चाहिए। संगठन की यह भी अनुशंसा है कि प्रति 1000 जनसंख्या पर पांच अस्पताल बिस्तर होने चाहिए। विकसित देशों के बुनियादी ढांचे तथा भारत में मौजूदा व्यवस्था के बीच जो बड़ा अंतराल है उसे चित्र 1 के माध्यम से समझा जा सकता है।

चित्र 1: अस्पतालों में प्रति 1000 जनसंख्या पर बेड

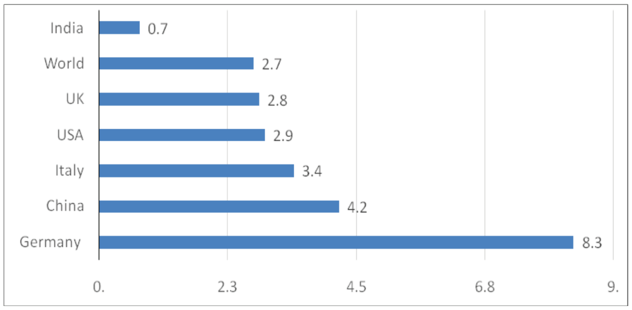

नोटः *उपलब्ध नवीनतम वर्ष के लिए लिया गया डेटा,*

स्रोतः *विश्व विकास संकेतक डेटासेट, विश्व बैंक*

देश के सामने मौजूद चुनौती को सही परिप्रेक्ष्य में उस समय समझा जा सकता है जब हमें इस बात का एहसास हो कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा सूचकांक पर भारत का स्कोर 2017 में 55 था जबकि इसका वैश्विक औसत 65.7 है। यह सूचकांक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच तथा उनके इस्तेमाल के सामर्थ की जानकारी देता है। इटली, जो कोविड–19 महामारी से जूझ रहा है, इस सूचकांक पर उसका स्कोर 82 है। हो सकता है कि अल्पकाल में ऊपर बताई गए समस्याओं का समाधान न ढूंढा जा सके लेकिन कम से कम इस दिशा में उठाए जाने वाले कुछ कदमों की पहचान तो की ही जा सकती है।

तात्कालिक प्राथमिकताएं

सबसे पहली और सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि चिकित्सा संबंधी आपूर्ति को बड़े पैमाने पर बढ़ाया जाए। इनमें सैनिटाइजर, डिसइनफेक्टेंट, फेस मास्क, सर्जरी वाले दस्ताने, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सुरक्षात्मक गियर,जांच किट, इंफ्रारेड थर्मोमीटर, स्कैनर, वेंटिलेटर, इनहेलर एवं अन्य वस्तुएं शामिल है। इनमें से कुछ ऐसी हैं जिनके लिए उच्च स्तरीय टेक्नॉलॉजी चाहिए पर इनमें से ज्यादातर के लिए इतनी उच्चस्तरीय टेक्नोलॉजी की आवश्यकता

नहीं है और आसानी से उनका निर्माण किया जा सकता है। ऐसे में परंपरागत दवाई व चिकित्सा उपकरण निर्माण उद्योग के अलावा औद्योगिक क्षेत्र के अन्य क्षेत्र भी इसमें योगदान कर सकते हैं। महामारी के आर्थिक प्रभावों के कारण ऑटोमोबाइल जैसी विलासिता पूर्ण एवं आरामदेह वस्तुओं की मांग कम हो रही है। हमारे पास हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड जैसे औद्योगिक इकाइयां हैं जो बड़ी आसानी से दस्ताने, मास्क आदि का निर्माण शुरू कर सकती हैं अमेरिका में जनरल मोटर्स तथा अंतर्वस्त्रों को बनाने वाली कंपनी हेन्स ब्रांड्स अब दस्तानों और मास्क का उत्पादन कर रहे हैं। भारत में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने पहले ही इस बात की घोषणा कर दी है कि वह भी जनरल मोटर्स की तर्ज पर ही ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। मारुति उद्योग लिमिटेड अपनी इकाइयों को बंद करने के बजाय, जिससे हजारों लोग बेरोजगार होंगे तथा जीडीपी पर असर पड़ेगा, इसी राह पर चल सकता है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य व आर्थिक विकास इन दोनों लक्ष्यों को साथ लेकर चलने के लिए एमएसएमई जैसे सेक्टर पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। संकट की इस स्थिति को एमएसएमई के लिए अवसर में बदला जा सकता है। इसके लिए उन्हें हल्की टेक्नोलॉजी वाली वस्तुओं के उत्पादन मसलन चिकित्सा व सफाई उपकरण जैसे मास्क, दस्ताने, रुई आदि के उत्पादन के लिए विशेष प्रोत्साहन देना होगा। इससे ठहराव में आ चुका यह क्षेत्र भी दोबारा अपनी राह पर लौट सकेगा।

जहां तक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे की बात है, हालांकि हमने एक बड़ा बुनियादी ढांचा जनसंख्या वृद्धि के कारण स्थापित कर दिया है लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच प्रति व्यक्ति के आध ार पर बहुत सीमित है। देखें तालिका एक। तात्कालिक मांग, ज्यादा से ज्यादा आइसोलेशन कैंप जिनमें न्यूनतम सुविधाएं होंगी, के लिए होगी। फिलहाल तो इटली और यूके जैसे देश जहां भारत की तुलना में स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा बहुत बेहतर है उन्हें भी कोविड–19 के सभी रोगियों को संभालने में मुश्किल आ रही है। भारत में आपातकालीन कदम के तौर पर बड़ी संख्या में ट्रांजिट अथवा आइसोलेशन फैसिलिटी, क्वॅरेंटाइन के लिए स्थापित की जा सकती हैं। भारत की जनसंख्या के आकार को देखें तो शायद हमें यह देखना होगा कि प्रत्येक ऐसा केंद्र 3000 से 5000 मरीजों को अपने यहां रख सकने की क्षमता रखता हो और एक केंद्र 10 लाख की जनसंख्या के लिए पर्याप्त हो। भारत अभी भी संक्रामक रोगों व प्राकृतिक आपदाओं के खतरों का सामना कर रहा है। इस प्रकार ये नई सुविधाएं भविष्य में भी काम आ सकती हैं। केंद्र व राज्य सरकारों में बुनियादी ढांचे के लिए आवंटित राशि को संभवतः इन परियोजनाएं की ओर मोड़ना पड़ सकता है । पर अंततः देश के लिए अल्पकाल, मध्यावधिक तथा दीर्घकाल के लिए यह कदम कल्याणकारी साबित होगा।

जेनेरिक फार्मा व मानव संसाधन

भारत का दवाई क्षेत्र हमेशा से पूरी दुनिया के लिए सस्ती दवाओं का एक विश्वसनीय स्त्रोत रहा है। पर चीन में इस महामारी के आरंभ होने के बाद से इस उद्योग के लिए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इनग्रेडिएंट यानी एपीआई की आपूर्ति की कमी एक प्रमुख चुनौती के रूप में उभरी है। फिलहाल यह उद्योग उन दवाओं को बनाने पर फोकस कर सकता है जिसके लिए कच्चा माल तुरंत उपलब्ध है और इसके साथ ही वह इसे भारतीय आपूर्ति श्रंखला के साथ जोड़ सकता है, बिना इस बात का इंतजार किए कि वैश्विक मूल्य श्रंखला कब तक दोबारा पटरी पर लौटेगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कच्चे माल आदि की आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ता अंततः नुकसान में न रहें, खासकर तब जबकि वैश्विक मूल्य श्रृंखला एक–आध साल में पटरी पर लौट आती है। इसके लिए फर्मों को इन आपूर्तिकर्ताओं के साथ मध्यावधि के अनुबंध करने चाहिए। इस उद्योग को अपने स्तर पर एक परामर्श समूह बनाना चाहिए जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ तथा चिकित्सा से जुड़े विशेषज्ञ हों जो किसी महामारी के आरंभ होने के संदर्भ में जरूरतों को प्राथमिकता के आधार पर तय कर सके और उसी के अनुरूप उसका उत्पादन किया जा सके।

मानव संसाधनों को लेकर एक अलग प्रकार की समस्या है क्योंकि उन्हें बहुत ही कम समय के नोटिस पर तैयार नहीं किया जा सकता है। यह जरूर किया जा सकता है कि जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल किया जाए और उन्हें बिल्कुल ठीक जगह पर लगाया जाए। आपातकालीन स्थिति से कुछ मूलभूत सवाल भी खड़े होते हैं जैसे कि भारत जैसे देश को किस प्रकार के स्वास्थ्य कर्मी चाहिए। हमारी चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था को यह सुनिश्चित करना होगा कि हम ग्रामीण व शहरी समुदायों के लिए उच्च स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करवाने में सक्षम हों। यहां यह भी ध्यान रखना होगा कि उनकी खर्च वहन करने की क्षमता भी सीमित है। हमारे नीति निर्माताओं को इस मसले को गंभीरता से देखना होगा। यहां यह भी याद रखना होगा कि भारत अपने यहां चिकित्सा संबंधी शिक्षा को बड़े पैमाने पर सब्सिडी देता है। इसमें कुछ गलत नहीं है लेकिन हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सार्वजनिक कोष इस प्रकार से सबसे प्रभावी तरीके से खर्च हो जिससे विकास भी हो तथा आम आदमी को लाभ भी मिले। आवश्यकता है कि हम इस प्रकार का चिकित्सा शिक्षा मॉडल विकसित करें जिससे न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य की आवश्यकताएं पूरी हो बल्कि इससे हम अपने देश के फार्मास्युटिकल उद्योग को भी इतना बेहतर कर सकें ताकि वे राष्ट्र के विकास में बराबर के भागीदार बन सकें। कोविड–19 संकट से निपटने के तरीकों का दीर्घकाल प्रभाव होगा तथा इसके वैश्विक परिणाम भी है। फिलहाल सभी देश अपने अपने यहां की चुनौतियों से निपट रहे हैं। हालांकि प्रत्येक देश की परिस्थिति के अनुसार वहां का मॉडल विकसित होगा। भारत जैसा देश जहां कि दवाई उद्योग का जाल अच्छे से फैला हुआ है और जहां एक विकसित शिक्षा व्यवस्था भी है वह अपना मॉडल खुद बना सकता है। यह मॉडल राष्ट्र निर्माण का मॉडल हो सकता है और इसके लिए हमें सार्वजनिक स्वास्थ्य की आवश्यकता तथा अर्थव्यवस्था का संगम आपस में करना होगा जिससे कि राष्ट्र का विकास हो सके।

विजिटिंग फेलो, आरआईएस। रिसर्च एसोसिएट डा. दिनेश कुमार व रिसर्च असिस्टेंट श्री अपूर्व भटनागर की इनपुट्स के साथ।

कोविड–19 के बाद की दुनिया में औद्योगिकीकरण: भारत के लिए विकल्प

सब्यसाची साहा

जहां एक ओर कोविड–19 के संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ना मुश्किल साबित हो रहा है वहीं बाकी सारी आर्थिक गतिविधियां धराशायी होती नजर आ रही हैं। भूमंडलीकरण मानव सभ्यता की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। इसके अंतर्गत टेक्नॉलॉजी की शक्ति से बड़े पैमाने पर सीमाओं के आर पार वस्तुओं, पूंजी व लोगों का आवागमन संभव हुआ। यह निश्चित रूप से बदलने जा रहा है। उत्पाद की लागत तय करने वाले कई तथ्यों के कारण विभिन्न देशों में उत्पादन बढ़ गया था। वैश्विक स्तर पर आम सहमति के कुछ प्रयासों, अधिक पारदर्शिता व बहुपक्षीय संबंधो में भरोसे के कारण व्यापार और वित्त के कुछ ऐसे नियम कायदे बन गए जिससे कि उत्पादन व सेवाओं को उपलब्ध करवाने जुड़ी मूल्य श्रृंखलाओं में और गहराई आई। हालांकि हाल ही में ज्ञान तथा संसाधनों का स्वामित्व कुछ हाथों में केंद्रित होने के कारण इस भूमंडलीकरण के खिलाफ एक विरोध का स्वर भी उठ रहा था।

बड़े विकसित देशों के उभरने के साथ ही उच्च आय वाले देशों की पकड़ ढीली पड़ रही थी। जलवायु परिवर्तन तथा बढ़ती हुई असमानता जैसे चुनौतियों को ठीक प्रकार से न स्वीकार करने के कारण इन देशों का कद पहले से बहुत कम हो गया था। पिछले दशक में आए आर्थिक संकट वित्तीय संकट से यह बात स्पष्ट हो गई थी कि वैश्विक पूंजी सब को जोड़कर रखने वाला तत्व नहीं हो सकती है। इसके अलावा विकास के लिए आवश्यक वित्त मे लगातार कमी हुई, इसके कारण बहुस्तरीय बहुपक्षीय सुशासन की वैधता पर एक बड़ा संकट आ गया। अंतरराष्ट्रीय व्यापार पहले ही आपसी भरोसे में कमी आने के कारण कमजोर पड़ चुका है। हालांकि पिछले दशक में कई देशों ने अपनी पूरी ऊर्जा वैश्विक वित्तीय संकट से निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को दुरूस्त करने में खर्च की है लेकिन इसके बावजूद दुनिया आज पहले से ज्यादा अनिश्चित नजर आ रही है। ऐसे में कई देशों ने अंतर्मुखी होना शुरू कर दिया है। जहां कुछ विकासशील देशों ने भूमंडलीकरण का लाभ उठाते हुए तेजी से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर्ज की, वहीं कई अन्य देशों में इसे लेकर एक आशंका भी है और वे 'मध्यम आय के जाल' में फंसने से बचना चाहते हैं। कोविड–19 इससे ज्यादा खराब समय पर नहीं आ सकता था।

इतना तो निश्चित है की औद्योगिक उत्पादन के लिए जीवीसी को एक प्रमुख मॉडल अब नहीं माना जा सकता और जो देश इस मॉडल के साथ बहुत ज्यादा गहरे से नहीं जुड़े हैं उनका नुकसान भी कम होगा। लेकिन संसाधनों की उपलब्धता तथा इंटरमीडिएट इनपुट्स के स्त्रोत अभी भी दुनिया भर में विभिन्न देशों में बिखरे रहेंगे। कुछ समय से यह सवाल पूछा जा रहा था कि क्या जीवीसी एक स्थाई मॉडल है और मूल्य श्रंखला का घरेलुकरण किस हद तक संभव है। यह भी सच है कि मूल्य श्रृंखलाओं का मतलब विभिन्न देशों के लिए अलग अलग है और अब छोटे देश पार्ट्स और कंपोनेंट्स में विशेषज्ञता हासिल कर सकेंगे। बड़े पैमाने पर उत्पादन करने

से होने वाले लाभ के चलते नए मैन्युफैक्चरिंग हब कुछ मुट्ठी भर देशों में ही केंद्रित हो गए थे। जहां 'केंद्र और परिधि' के पुराने सिद्धांत को कम प्रासांगिक माना जा रहा था वही नयी असमानताएं भी उभर रही थी। दुनिया में इन असमानताओं को कम करने के लिए तनाव की एक नई लहर पैदा होगी। इसका कारण है उत्पादन का स्थानीयकरण तथा आजीविका सृजन पर ध्यान केंद्रित होना। बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से अब चीजें परिभाषित नहीं होंगी बल्कि प्रतिद्वंद्विता के नए स्रोत अब चीजों को परिभाषित करेंगे।

बड़े व्यवसायों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को नई वास्तविकताओं के साथ समायोजन करना होगा। उन्हें अपने लेखांकन के तरीकों को इस प्रकार से विस्तारित करना होगा जिससे कि सामाजिक व पर्यावरण संबंधी लागत एवं खतरों का भी संज्ञान लिया जा सके। इस प्रकार केवल उत्पादन के साधनों के संदर्भ में ही अब प्रतिद्वंद्विता या प्रतियोगिता को

परिभाषित नहीं किया जा सकता, जैसे–जैसे नई टेक्नालॉजी पर निर्भरता बढ़ेगी, वैसे ही देशों के लिए इन प्रौद्योगिकियों के स्त्रोतों से दूर रहना मुश्किल होगा। इसी प्रकार इन देशों के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा प्रोत्साहित किए गए परंपरागत व्यवसायिक मॉडलों से दूर रहना भी मुश्किल होगा। लेकिन बढ़ते खतरों के साथ ही ये व्यापार संरचना भी बदलने जा रही हैं और विभिन्न देशों में आपस में इस बात की दौड़ होगी कि कितनी जल्दी और बेहतर तरीके से वे अपनी क्षमताओं को और मजबूत कर सकते हैं। अल्पकालीन व दीर्घकालीन नीतियां स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में काम करेंगी। ऐसा कई देशों में होगा और खासकर उन क्षेत्रों में होगा जहां आत्मनिर्भरता की आवश्यकता है। इस संदर्भ में सफलता कैसे मिलेगी यह देखना अभी बाकी है।

इसके बाद भारत में औद्योगिक उत्पादन को लेकर क्या होने जा रहा है यह गहन विश्लेषण का विषय है। भारत के पास एक बड़ा बाजार है जिससे कि उसे सहारा मिल सकता है। लेकिन जैसा कि सुझाव दिया गया है भारत में औद्योगिक उत्पादन को कई गुना बढ़ने की जरूरत है। ऐसे में 'मेक इन इंडिया' पहले से कहीं ज्यादा अर्थपूर्ण है। इस संदर्भ में यह कहना भी आवश्यक है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे नए क्षेत्र में विस्तार के कारण एक नया आत्मविश्वास भी आया है। इस बात की संभावनाएं काफी अधिक हैं की एमएसएमई इकाईयों को सक्रिय समर्थन के साथ घरेलू आपूर्ति श्रंखला को बेहतर भी किया जा सकता है और उनमें ज्यादा स्थायित्व भी लाया जा सकता है। भारत को और अधिक बेहतर प्रतियोगी बनाने में यह महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं हालांकि दूसरे देशों में भी कुछ इसी प्रकार की नीतिगत पहल की जा रही है। गुणवत्ता, स्थायित्व व रणनीति फर्म के स्तर पर महत्वपूर्ण कारक साबित होंगे और इन्हें सरकारी नीतियों के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। पूंजीगत वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटो, एफएमसीजी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स तथा संसाधन आधारित उद्योग महत्वपूर्ण होंगे। जब तक दुनिया में वापस व्यापार अपनी गति नहीं पकड़ लेता तब तक हमारा फोकस एक दीर्घकालीन रणनीति पर होना चाहिए जिसके केंद्र में अपने विकल्पों को और विविधतापूर्ण करना तथा टेक्नॉलॉजी कंटेंट को और सघन करना होगा जिससे कि अधिक प्रीमियम कमाए जा सके। अभी तक हमारी औद्योगिक संभावनाओं का पूरा दोहन नहीं किया जा सका है। मानव विकास, कौशल निर्माण तथा मजबूत प्रौद्योगिकी से हमारी औद्योगिक क्षमता में वृद्धि होगी जिससे हम अब तक की संभावनाओं का पूरा दोहन कर सकेंगे। जहां अर्थव्यवस्था को इस वायरस से अपना अस्तित्व बचा कर रखना है सरकार ने अपनी शुरुआती प्रतिक्रिया में अपनी सकारात्मक मंशा भी जाहिर की है। एक साल पूर्व राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी की घोषणा की गई थी। मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम–ईमएसमी 2.0–को सरकार ने वित्तीय सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा विकसित करने में मदद मिलेगी। इस मौके पर इस प्रकार की नीतिगत पहल बहुत आवश्यक है। इससे उद्योगों के स्थान परिवर्तन तथा घरेलु उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा।

सहायक प्रोफेसर, आरआईएस

कोविड–19: भारतीय वित्तीय क्षेत्र में अनिश्चितता के बढ़ने की संभावना

प्रियदर्शी दाश

कोरोना वायरस महामारी, कोविड–19 ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर अनिश्चितता का माहौल बना दिया है। आर्थिक मंदी के पिछले किसी भी प्रकरण की तरह इस महामारी का भी प्रतिकूल प्रभाव वित्तीय सेक्टर पर होगा। इसी वजह से भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने 3.74 खरब रुपयों की मदद का ऐलान किया जिसमें कि सभी सेक्टरों को मदद मिलेगी। इससे पूर्व कभी भी आरबीआई ने बैंकों को दिए जाने वाले ऋण पर ब्याज दर को 75 बेसिस पॉइंट्स कम नहीं किया है। एक अन्य प्रमुख घोषणा के अनुसार सभी प्रकार के ऋणों की किश्तों जिसमें कि कृषि ऋण भी शामिल हैं, के भुगतान को स्थगित करना। यह नियम सभी ऋणों पर लागू होगा जिनमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों व स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, कोऑपरेटिव बैंकों, शेड्यूल्ड बैंकों तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा दिए गए ऋण शामिल हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा दिए गए ऋणों में आवासीय कंपनियों तथा माइक्रोफाइनेंस संस्थानों द्वारा दिए गए ऋण भी शामिल हैं[1]।

ये उपाय अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्रों में निधि प्रवाह में व्यवधान को कम करने, व्यवसायों के लिए कार्यशील पूंजी की कमी से बचने और बैंकों और गैर–बैंकिंग जमा लेने वाली संस्थाओं से घबराहट में जमा राशि निकलवाने की प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए है। विश्वास निर्माण के इन उपायों का विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा पूंजी को बाहर ले जाने के प्रयासों तथा बाहरी वाणिज्यिक ऋणों की कमी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कार्यशील पूंजी ऋण को नए सिरे से व्यवस्थित करने का कदम विशेष रूप से एसएमई वित्तपोषण को सहायता प्रदान करेगा तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं में बड़े व्यवधानों को कम करेगा।

पहले से ही विश्व अर्थव्यवस्था में वित्तीय क्षेत्र में ठहराव की आशंका को ध्यान में रखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंक और बैंक फॉर इन्टरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस) और बहुपक्षीय विकास बैंक (एमडीबी) जैसे प्रमुख वैश्विक वित्तीय संस्थान जैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी), एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी), आदि ने वैश्विक आर्थिक विकास में और मंदी का सामना करने के लिए विभिन्न वित्तपोषण सहायता पैकेजों की घोषणा की है। इसके अलावा, आईएमएफ और विश्व बैंक ने स्वयं को किए जाने भुगतान में देरी को अनुमति देकर विकासशील देशों के ऋण बोझ को कम करने की घोषणा की है।

आरबीआई पैकेज के बावजूद, भारतीय बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र को आने वाले महीनों में कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्र जैसे यात्रा, आतिथ्य और परिवहन और रसद बुरी तरह से प्रभावित हैं। वाणिज्यिक बैंकों और गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के उन क्षेत्रों में आने वाले दिनों में ऋण जोखिम धीरे–धीरे खराब संपत्ति में बदल सकते हैं।

पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बैंक और यस बैंक के संकट के कारण भारतीय वित्तीय प्रणाली में विश्वास के क्षरण को कोविड–19 और बढ़ा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र में गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) की मात्रा में महत्वपूर्ण वृद्धि की चुनौती को निपटाने से पहले, बैंकिंग नियामक, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) को पीएमसी और यस बैंक क्रेडिट में प्रणालीगत नियामक पतन का सामना करना पड़ा था। इससे बैंकिंग क्षेत्र के स्वास्थ्य और लचीलेपन को लेकर मिले संकेत चिंताजनक थे।

आरबीआई द्वारा दिसंबर 2019 में प्रकाशित वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार, "३ कमजोरियों के स्रोत लगातार एक दूसरे के साथ मिलकर व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं", जिसने शायद बैंकिंग क्षेत्र को हाल के वर्षों में समायोजनकारी मौद्रिक नीति को आगे बढ़ाने की अनुमति दी थी।

यह रिपोर्ट थोक ऋण वृद्धि में गिरावट और अर्थव्यवस्था के वास्तविक क्षेत्रों पर मौद्रिक नीति आवेगों के प्रभाव से पैदा हुई चुनौतियों को रेखांकित करती है। दूसरी तरफ डिजिटल धन के उपयोग में तेज वृद्धि से घरेलू वित्तीय परिदृश्य बेहतर हो सकता है। भारतीय वित्तीय क्षेत्र में काविड–19 से संबंधित अव्यवस्था के आकलन का अध्ययन दो कोणों से किया जा सकता है: पहला वह जो पिछले कुछ महीनों में पहले से निर्मित जोखिमों को और बढ़ा देंगे, और दूसरा वह जो वैश्विक आर्थिक झटके से निकलने वाली नई चुनौतियाँ जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई), निर्यात से होने वाली आय तथा बाहर भारत में हस्तांतरित होने वाली आय में भारी गिरावट के रूप में सामने आएंगी।

पहली चुनौती की बात करें तो, सात साल की गिरावट के बाद पूंजी की पर्याप्त उपलब्धता, तरलता और संपत्ति की गुणवत्ता के मामले में बैंकिंग क्षेत्र में ध्यान देने योग्य सुधार के बावजूद, भारतीय बैंकिंग पूरी तरह से चुनौतियों से मुक्त नहीं है। एनपीए की अधिकता और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकिंग द्वारा कम ऋण वृद्धि (2018–19 के दौरान क्रेडिट वृद्धि मुख्य रूप से निजी बैंकों द्वारा सहायता प्राप्त थी) प्रणाली में जोखिमों के निर्माण को इंगित करता है जो आगे की मांग और व्यावसायिक गतिविधि में कटौती होने पर आगे बिगड़ सकती है।

ऋण जोखिम के लिए मैक्रोज–स्ट्रेस टेस्ट से संकेत मिलता है कि सितंबर 2019 में 9.3 प्रतिशत एनपीए सितंबर 2020 में बढ़कर 9.9 प्रतिशत हो सकता है। इन आंकड़ों को भी संशोधित करना पड़ सकता है। एक सकारात्मक बिंदु जो भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लचीलेपन में योगदान देता है, वह इसके प्रावधान कवरेज अनुपात , स्थिर तरलता कवरेज अनुपात (एलसीआर) और नेट स्टेबल फंडिंग अनुपात (एनएसएफआर) में उल्लेखनीय सुधार के साथ बेसल–3 नियमों का अनुपालन है। इसके अलावा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के पूंजीगत जोखिम–आधारित संपत्तियों का अनुपात (सीआरएआर) 2014–15 में 13 प्रतिशत से सुधार करके 2019–2020 की पहली छमाही में 15.1 प्रतिशत हो गया।

इसी तरह, भारतीय बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के लिए जोखिमों का दूसरा कारण वैश्विक झटकों का तेजी से फैलने वाला प्रभाव है। भारत के निर्यात ने 11 महीनों में फरवरी 2020 तक 292.9 बिलियन डॉलर को छू लिया था, जबकि आयात 436.03 बिलियन डॉलर था। लेकिन ये निश्चित रूप से 2020–21 तक बहुत कम हो जाएंगे। इस बीच 27 मार्च तक, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजारों से 58,408.15 करोड़ रुपये निकाले हैं[2]।

एक ही दिन में बीएसई सेंसेक्स 4000 अंक टूट गया था। इन सभी घटनाक्रमों से मंदी और ज्यादा खराब स्थिति में पहुंचेगी जिससे वाणिज्यिक बैंकिंग प्रभावित होगी। इसके अलावा, भारतीय रुपए के मूल्यह्रास से चालू खाते का संतुलन बिगड़ सकता है, हालांकि तेल की कीमतों में कमी से कुछ राहत मिली है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अभी भी स्थिर है और 21 दिन के लॉक–डाउन के बीच भोजन, सब्जियों, दवाओं आदि सभी आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक को लेकर फिलहाल कोई समस्या नहीं है।

आर्थिक गतिविधियों में गिरावट और कर राजस्व में गिरावट का एक अर्थ यह है कि सरकार की राजकोषीय स्थिति तब बाधित होगी जब आरबीआई और वित्त मंत्रालय इस सप्ताह अपना ऋण कैलेंडर जारी करेंगे।

इसी समय आरबीआई के लिए यह आवश्यक हो सकता है कि बीमारी के फैलने तक भविष्य के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर फिलहाल रोक लगाई जाए। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सरकारी व्यय का अधिक आवंटन चिकित्सा आपूर्ति और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे पर खर्च के रूप में सामने आएगा, जो अन्य क्षेत्रों में पूंजीगत व्यय को काफी हद तक स्थगित कर देगा। भारत को एआईआईबी और एनडीबी से आपातकालीन कोविड–19 फंडिंग के रूप में सहायता की खोज करने की आवश्यकता हो सकती है। एआईआईबी ने आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति जारी करके चीन को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया जबकि एनडीबी ने आरएमबी 7 बिलियन आपातकालीन सहायता पैकेज बढ़ाया। कुल मिलाकर कोविड–19 के लिए योजनाबद्ध ढंग से किए जा रहे प्रयासों को जारी रखने के लिए, भारतीय वित्तीय क्षेत्र को आने वाले दिनों में कठिन समय के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है।

संदर्भ

1 कोविड–19 – विनियामक पैकेज (संशोधित), आरबीआई, मार्च 27,2020 https://www.rbi.org.in/Scripts/NotificationUser.aspx?Id=11835&Mode=0

2 एफआईआई और डीआईआई कारोबार की सक्रियता मार्च 20, मनी कंट्रोल; https://www-moneycontrol-com/stocks/ Marketstats / fii_dii_activity / index-php

सहायक प्रोफेसर, आरआईएस

RIS
Research and Information System
for Developing Countries
विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली

कोर 4–बी, चौथा तल, भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड, नई दिल्ली–110 003, भारत । दूरभाष: 91-11-24682177-80
फैक्स: 91-11-24682173-74, ई–मेल: dgoffice@ris.org.in
वेबसाइट: http://www.ris.org.in

Follow us on:

www.facebook.com/risindia

@RIS_NewDelhi

www.youtube.com/RISNewDelhi

प्रबंध संपादक: तीश मल्होत्रा